राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रकाशित एवं ई गवर्नेंस बुलेटिन

वॉल्यूम 30, सं 4, अप्रैल, 2022

इंफोर्मेटिक्स

संपादकीय संयोजन : प्रिस्का लाकड़ा

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम–किसान पहल के तहत 10.09 करोड़ से अधिक किसानों को 20,900 करोड़ रुपये एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा के माध्यम से जारी किये

माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी, एनआईसी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा के माध्यम से वस्तुतः वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी करते हुए

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2022 को पीएम-किसान वेब पोर्टल (https://pmkisan.gov.in) के आईसीटी समाधान का उपयोग करके वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत 10.09 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 20,900 करोड़ रुपये) से अधिक की वित्तीय लाभ की 10 वीं किस्त जारी की। कार्यक्रम के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री ने लगभग 351 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को 14 करोड़ रुपये से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया, जिससे 1.24 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा।

पीएम-किसान सम्मान निधि पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और 24 फरवरी 2019 को माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। तब से, इसने माननीय वन और पर्यावरण मंत्री, श्री जेम्स पीके संगमा को स्थानांतरित करने में मदद की है, मेघालय पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर फंड के लिए मोबाइल और वेब एप्लिकेशन सीधे किसान परिवारों के खातों में लॉन्च किए हैं। यह पीएम-किसान योजना के तहत पंजीकृत किसानों के खातों में सीधे लाभ हस्तांतरित करने के लिए एक एंड-टू-एंड प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करता है।

इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे उपस्थित थीं। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों, कृषि मंत्रियों और किसानों को जोड़ा गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने एफपीओ के साथ बातचीत की।

– सूचना-विज्ञान समाचार डेस्क, एनआईसी-मुख्यालय

माननीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री श्रीमती सत्यवती राठौड़ तेलंगाना सरकार द्वारा आरोग्य लक्ष्मी डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ

श्रीमती सत्यवती राठौड़, माननीय अनुसूचित जनजाति कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री और श्रीमती डी दिव्या, आईएएस, विशेष सचिव और आयुक्त, डब्ल्यूडीसीडब्ल्यू विभाग, श्री के. राजशेखर, डीडीजी और एसआईओ, तेलंगाना राज्य इकाई की उपस्थिति में 3 जनवरी 2022 को आरोग्य लक्ष्मी डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। इस एप्लिकेशन को एनआईसी तेलंगाना द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।

इस कार्यक्रम में श्री एस कृष्णा, एसटीडी, एनआईसी टीएसयू और अन्य अधिकारियों ने डब्ल्यूडीसीडब्ल्यू विभाग, तेलंगाना के कर्मचारियों के साथ भाग लिया। माननीय मंत्री श्रीमती सत्यवती राठौड़ और श्रीमती डी दिव्या, आईएएस ने एनआईसी द्वारा किए गए योगदान की सराहना की।

– बीना सी, तेलंगाना

श्रीमती सत्यवती राठौड़, माननीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री, और श्रीमती डी. दिव्या, आईएएस, विशेष सचिव और आयुक्त, डब्ल्यूडीसीडब्ल्यू विभाग, तेलंगाना सरकार के साथ श्री के. राजशेखर एसआईओ तेलंगाना

पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य के व्यापार करने में आसानी के लिए एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ किया

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम और वस्त्र विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के तहत व्यापार में आसानी के लिए - एनआईसी, पश्चिम बंगाल द्वारा एकीकृत (ईओडीबी) पोर्टल को डिजाइन और विकसित किया गया ।

माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बैनर्जी द्वारा एक उच्च स्तरीय व्यावसायिक घरानों, सीआईआई के सदस्यों, बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, प्रेस और मीडिया हाउस के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इस पोर्टल का उद्घाटन किया गया । मुख्य सचिव, डॉ एचके द्विवेदी, आईएएस ने राज्य में संभावित उद्यमियों के लिए ईओडीबी पोर्टल की उपयोगिता पर प्रकाश डाला।

पोर्टल (https://wbmsme.gov.in/sid) राज्य में उद्यम स्थापित करने के लिए अनिवार्य विभिन्न लाइन विभागों से अनुमोदन, अनुपालन और मंजूरी पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है। आवेदक पोर्टल से ही विभिन्न लाइन विभागों की सभी 101 (एक सौ एक) ई-सेवाओं को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। आवेदक ''अपने अनुमोदन को जानें'' के तहत प्रश्नावली के एक सरल सेट के माध्यम से आवश्यक अनुमोदन के बारे में पोर्टल से एक उचित विचार प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है जैसे अनिवार्य समय जिसके तहत एक सेवा प्रदान की जाती है, विभागीय सुधार जो ईओडीबी और शिकायत निवारण प्रणाली के तहत सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किए गए थे।

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम और वस्त्र विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के तहत व्यापार करने में आसानी के लिए एक एकीकृत (ईओडीबी) पोर्टल का उद्घाटन

- मोतिउर रहमान, पश्चिम बंगाल

माननीय शहरी विकास मंत्री, हिमाचल प्रदेश ने एचपी रेरा पोर्टल का शुभारंभ किया

श्री सुरेश भारद्वाज, माननीय शहरी विकास मंत्री, हिमाचल प्रदेश ने 7 जनवरी 2022 को शिमला में हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट अथॉरिटी के वेब पोर्टल का शुभारंभ किया । डॉ. श्रीकांत बल्दी, अध्यक्ष, एचपी रेरा, श्री बीसी बडालिया, सदस्य (प्रशासन), श्रीमती नीरज कुमारी चांदला, संयुक्त सचिव आवास, श्री अजय सिंह चहल, एसआईओ एनआईसी एचपी, श्री मंगल सिंह, वैज्ञानिक-सी और अन्य अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

डॉ. श्रीकांत बल्दी ने इस व्यापक, संशोधित नागरिक केंद्रित और उपयोगकर्ता के अनुकूल वेब पोर्टल की विभिन्न विशेषताओं के बारे में लॉन्च समारोह के दौरान एक व्यापक प्रस्तुति दी। एचपी रेरा का प्राथमिक उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण घरों/ फ्लैटों के साथ रियल एस्टेट खरीदारों में पारदर्शिता लाना और विश्वास पैदा करना, समय पर डिलीवरी, शिकायतों का त्वरित समाधान और परियोजना को चलाने के लिए समय पर अनुमोदन हेतु पूर्व-सुविधा और ऑनलाइन शिकायतों/चिंताओं को दर्ज करना है। पोर्टल में एजेंटों, बिल्डरों, डेवलपर्स, नागरिकों और मालिकों के लिए सुविधाएं हैं। इसका उद्देश्य ऑनलाइन मोड में सभी सेवाएं प्रदान करना, भुगतान गेटवे के माध्यम से भुगतान स्वीकार करना और एसएमएस और ईमेल के माध्यम से अलर्ट प्रदान करना है ताकि एचपी रेरा कार्यालय में भौतिक रूप से जाने की आवश्यकता न हो। नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से अचल संपत्ति परियोजनाओं, प्रमोटरों और एजेंटों को कई मापदंडों के आधार पर खोज सकते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एचपी रेरा के सभी ऑर्डर ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं।

माननीय यूडी मंत्री, हिमाचल प्रदेश ने एचपी रेरा पोर्टल का शुभारंभ किया

- अजय सिंह चहल, हिमाचल प्रदेश

माननीय वन और पर्यावरण मंत्री, मेघालय ने मेघालय के पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर के लिए मोबाइल और वेब एप्लिकेशन लॉन्च किए

माननीय वन और पर्यावरण मंत्री, मेघालय सरकार, श्री जेम्स पीके संगमा ने 24 फरवरी 2022 को मुख्य सचिवालय शिलांग मेघालय सम्मेलन हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में मेघालय जैव विविधता बोर्ड के लिए मेघालय पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) के मोबाइल और वेब एप्लिकेशन लॉन्च किए। पीबीआर प्रत्येक गांव की जैव विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) सहित गांव की साख के साथ गांव-वार व्यवस्थित करने के लिए राज्य के समृद्ध वनस्पतियों और जीवों की एक सूची है। पीबीआर वेब ऐप को राज्य के जैविक संसाधनों के इन्वेंट्री डेटाबेस को अद्यतन और समृद्ध करने के लिए एनआईसी द्वारा विकसित किया गया था, जिससे मोबाइल ऐप का उपयोग न केवल डोमेन से संबंधित अधिकारियों द्वारा बल्कि आम जनता द्वारा जो हमारी समृद्ध जैविक विरासत के दस्तावेजीकरण के लिए पूरक ओर अनुपूरक डेटा कैप्चर का कार्य करता है, के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो हमारे गांवों (जैव संसाधन मालिकों) के साथ लाभों के उचित और समान साझाकरण में मदद करेगा।

माननीय मंत्री ने इसमें एनआईसी और मेघालय जैव विविधता बोर्ड द्वारा किए गए तकनीकी हस्तक्षेप के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आगे दोहराया कि राज्य की प्रत्येक विकासात्मक योजना को इसकी समृद्ध जैव विविधता पर विचार करना चाहिए और इसके संरक्षण का भी प्रयास करना चाहिए। मेघालय पीबीआर का वेब अनुप्रयोग सभी के लिए एक तैयार संदर्भ के रूप में काम आएगा ।

माननीय वन और पर्यावरण मंत्री, श्री जेम्स पीके संगमा ने मेघालय के पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर के लिए मोबाइल और वेब एप्लीकेशन लॉन्च किया

- कैंडिडा बीएम बूथ शादप, मेघालय

आयुक्त (एमएएचयूडी), मणिपुर ने अमृत के तहत मणिपुर के 27 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 3 ऑनलाइन नगरपालिका सेवाएं शुरू कीं

मणिपुर के 27 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की तीन ऑनलाइन सेवाएं को एनआईसी मणिपुर द्वारा एनआईसी के सर्विसप्लस फ्रेमवर्क पर कॉन्फिगर किया गया था जिसे 18 जनवरी 2022 को आयुक्त, नगर प्रशासन आवास और शहरी विकास (एमएएचयूडी) विभाग, मणिपुर सरकार द्वारा श्री लैशराम श्यामजीत सिंह, एसआईओ मणिपुर, श्री रॉबर्ट क्षेत्रिमयम, आईएएस, निदेशक, एमएएचयूडी विभाग, मणिपुर सरकार और श्रीमती युमनाम नर्मदा देवी, मुख्य नगर योजनाकार/राज्य मिशन निदेशक (अमृत), नगर नियोजन विभाग, मणिपुर सरकार की उपस्थिति में लॉन्च किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और एनआईसी दिल्ली के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समारोह में शामिल हुए।

एनआईसी पर सर्विसप्लस फ्रेमवर्क का उपयोग करके ऑनलाइन सेवा के कार्यान्वयन के लिए नगर नियोजन विभाग मणिपुर द्वारा पहचानी गई पांच सेवाओं में से तीन का उद्घाटन किया गया। ये तीन सेवाएं हैं 1. जन्म प्रमाण पत्र जारी करना, 2. मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना और 3. टैंकों की बुकिंग और भुगतान करना।

इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोलते हुए, श्री विष्णु चंद्र, डीडीजी और एचओजी, आवास और शहरी मामले, एनआईसी दिल्ली ने यूएलबी की ऑनलाइन सेवा शुरू करने और लोगों को इन सेवाओं का ऑनलाइन लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए मणिपुर सरकार की सराहना की। आगे आयुक्त, एमएएचयूडी, मणिपुर सरकार और एसआईओ, एनआईसी मणिपुर ने ऑनलाइन (एंड टू एंड) सेवाओं के महत्व पर प्रकाश डाला। इन सेवाओं को ऑनलाइन भुगतान, एसएमएस और ईमेल अधिसूचना सुविधाओं के साथ एकीकृत किया गया है और इससे नागरिकों को बहुत लाभ होगा क्योंकि लोगों को अब स्वयं नगरपालिका कार्यालयों में आने की आवश्यकता नहीं होगी। शेष सेवाएं जल्द ही शुरू की जाएंगी।

एमएएचयूडी आयुक्त अमृत योजना के तहत 3 ऑनलाइन सेवाओं का षुभारंभ करते हुए

– एम. बुधिमाला देवी, मणिपुर

माननीय मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला जिले के लिए वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने 30 दिसंबर 2021 को जिला न्यायालय परिसर, शिमला में एक भव्य समारोह में शिमला जिले के लिए वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्रीमती न्यायमूर्ति सबीना, न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल, न्यायमूर्ति संदीप शर्मा, न्यायमूर्ति सी.बी. बरोवालिया, न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ, न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अन्य प्रतिष्ठित न्यायाधीश उपस्थित थे। वर्चुअल कोर्ट (https://vcourts.gov.in) आम जनता को न्यायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-समिति के प्रयासों में एक छलांग है। यह प्रणाली अदालत को घर पर लाती है जिससे जनता को मामले के विवरण तक पहुंचने, जुर्माना भरने और घर के आराम से मामलों को बंद करने की इजाजत मिलती है। यह सेवा स्थिर इंटरनेट कनेक्शन वाले सभी प्रकार के उपकरणों के माध्यम से सुलभ है ।

माननीय मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला जिले के लिए वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन करते हुए

– अजय सिंह चहल, हिमाचल प्रदेश

मेरा घर मेरे नाम (एमजीएमएन) पोर्टल, राजस्व विभाग, पंजाब सरकार

राजस्व विभाग, पंजाब ने राज्यव्यापी पोर्टल के विकास द्वारा राज्य में एमजीएमएन योजना की अवधारणा, विकास और कार्यान्वयन के लिए एक सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) पुस्तिका जारी की है।

एमजीएमएन पोर्टल एमजीएमएन कार्यान्वयन के सभी पहलुओं को कवर करेगा जिसमें राजस्व विभाग, पीएलआरएस, भारतीय सर्वेक्षण और एनआईसी जैसे विभिन्न हितधारकों की भूमिका शामिल होगी। जीआईएस पर एनआईसी पंजाब के सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के ब्लूप्रिंट और तकनीकी सहयोग के साथ-साथ एनआईसी पंजाब की भूमिका को प्रमुख स्थान दिया गया है।

एमजीएमएन लाल डोरा में वैध मालिकों/ रहने वालों को संपत्ति के अधिकार देने के लिए पंजाब सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। एनआईसी पंजाब को पंजाब आबादी देह (अधिकारों का रिकॉर्ड) नियम, 2021 के अनुसार वर्कफ्लो आधारित सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन/ पोर्टल विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में सौंपा गया है, ताकि गांव में लाल डोरा के भीतर घरों में रहने वाले निवासियों को संपत्ति के स्वामित्व के प्रबंधन और निगरानी की सुविधा मिल सके। यह उन्हें ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम करेगा और संपत्तियों को बिक्री योग्य और बिक्री योग्य बनाने का अधिकार प्रदान करेगा। वेब पोर्टल का उपयोग करके, मालिक संपत्ति की खोज कर सकता है और संपत्ति कार्ड भी डाउनलोड कर सकता है। सॉफ्टवेयर को चरणों में विकसित किया जाएगा, शुरू में सर्वेक्षण इकाई के नक्शे के साथ एकीकरण, अधिकारों का रिकॉर्ड बनाने के लिए। बाद में एक संपत्ति बंधक, बिक्री विलेख और अद्यतन उत्परिवर्तन के लिए प्रावधान किया जाएगा। जीआईएस पोर्टल और डिजिलॉकर के साथ एकीकरण की परिकल्पना बाद के चरणों में की गई है।

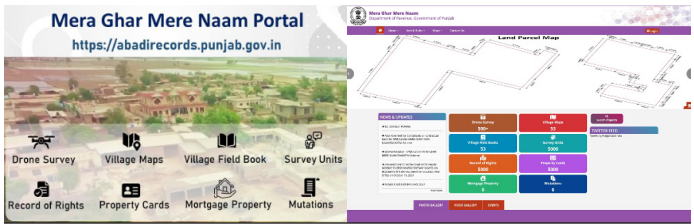

मेरा घर मेरे नाम (एमजीएमएन) पोर्टल डैशबोर्ड

– परमिंदर कौर, पंजाब

असम के माननीय मुख्यमंत्री ने 10 ऑनलाइन संपर्क रहित वाहन और सारथी सेवाओं की शुरुआत की

असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने 19 फरवरी 2022 को असम राज्य के परिवहन मंत्री श्री चंद्र मोहन पटवारी की उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से दस और ऑनलाइन संपर्क रहित नागरिक सेवाएं शुरू कीं। इन सेवाओं के अतिरिक्त, अब असम में कुल 13 संपर्क रहित नागरिक सेवाएं चालू हैं। इन सेवाओं में लर्नर लाइसेंस, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), स्वामित्व का हस्तांतरण, दृष्टिबंधक जोड़ना, दृष्टिबंधक रद्द करना, पंजीकरण प्रमाणपत्र में पता बदलना, वाहन में अनापत्ति प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, वाहन के वर्ग (सीओवी) का समर्पण, ड्राइविंग लाइसेंस निकालने और ड्राइविंग लाइसेंस का प्रतिस्थापन जैसी सेवाएं शामिल हैं।

इस अवसर पर अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे सितंबर और अक्टूबर 2021 में पहले शुरू की गई तीन संपर्क रहित सेवाओं के परिणामस्वरूप असम के जिला परिवहन कार्यालयों (डीटीओ) में लगभग 9 लाख फुटफॉल में कमी हुई थी और वैश्विक महामारी COVID-19 के बावजूद विभाग द्वारा राजस्व संग्रह में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

माननीय मुख्यमंत्री ने वाहन और सारथी की ऑनलाइन संपर्क रहित नागरिक सेवाओं को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, इस पर कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की। उन्होंने सुझाव दिया कि आवेदनों के सभी ऑनलाइन सत्यापन और अनुमोदन केवल मूल के डीटीओ को निर्देशित नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि डीटीओ के वर्तमान कार्यभार के आधार पर अन्य डीटीओ को भी यादृच्छिक रूप से सौंपे जाने चाहिए। इससे न केवल काम का अधिक समान वितरण होगा और पूरी प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि बिचौलियों द्वारा किसी भी हस्तक्षेप को समाप्त करना क्योंकि यह ज्ञात नहीं होगा कि कौन से डीटीओ आवेदन को सत्यापन और अनुमोदन के लिए सिस्टम द्वारा संदर्भित किया जाएगा।

– कविता बरकाकोटी, असम

असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा वाहन और सारथी की 10 ऑनलाइन संपर्क रहित नागरिक सेवाओं के शुभारंभ किया

'नियो क्रैडल वेब पोर्टल' का शुभारंभ – केरल में नियो क्रैडल केयर पर सूचना का भंडार

उद्घाटन समारोह के दौरान गणमान्य व्यक्ति

श्रीमती वीना जॉर्ज, माननीय स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास मंत्री, केरल सरकार ने नीला ऑडिटोरियम, मातृ शिशु और स्वास्थ्य संस्थान में नियो क्रैडल (https://neocradle.kerala.gov.in) का कोझीकोड में 5 जनवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम श्री पीए मोहम्मद रियास, माननीय पीडब्ल्यूडी और पर्यटन मंत्री, श्री मोहन कृष्णन पीवी, राज्य सूचना अधिकारी, और विभाग एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया था । राज्य सूचना अधिकारी केरल ने अभिनंदन भाषण दिया और ई-गवर्नेंस में एनआईसी की भूमिका के बारे में बताया ।

नियो क्रैडल संयुक्त रूप से जिला प्रशासन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), कोझीकोड और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, कोझीकोड द्वारा विकसित किया गया है। इसमें पूरे कोझीकोड जिले में मातृ और नवजात देखभाल के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। यह राज्य में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नवजात जटिलताओं और मृत्यु दर की घटनाओं को कम करना, नवजात परिवहन का मानकीकरण और नवजात गहन देखभाल इकाई (एनआईसीयू) के कर्मचारियों की क्षमता निर्माण करना है। समन्वित संचार प्रणाली और नेटवर्क के लिए जिले के सभी वितरण बिंदु इस परियोजना का हिस्सा हैं।

– आशा वर्मा, सूसी एम, केरल

देशभर में ई-शासन गतिविधियों के बारे में नवीनतम व अद्यतन समाचारों व सूचना के लिए News पर जायें https://informatics.nic.in/news